(c) With the strengthening of financial health of the Primary Coop. Societies through the revised scheme, the weavers would benefit in terms of employment, sustained production and higher wages.

(d) The incident of accumulation of stocks which used to be reported in the past will gradu-
. ally diminish.

Outstanding dues of Gujarat Government with NTC

4467. SHRI RAJUBHAI A. PAR-MAR: WL1 the Minister of TEXTILES be pleased ta state:

(a) the details of he outstanding dues from National Textile Corporation to the Gujarat Government as on December, 1994;

(b) the reasons for non-payment of the dues; and

(c) by when the dues are expected to be paid to the Gujarat Government?

THE MINISTER OF TEXTILES (SHRI G. VENKAT SWAMY); (a) As on 31.12.94, NTC owes an amount of Rs. 18.89 crores covering cotton dues and dues pertaining to ESI, electricity, municipal taxes and other taxes.

(b) and (c) NTC has been facing an acute working capital shortage. NTC is expected, to clear the . outstanding dues depending upon the availability of working capital.

कपास उत्पादकों को उचित मूल्य

4468. श्री संघ प्रिय गौतम : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश और गुजरात के कई कपास उत्पादक जिन्हें अपने उत्पादों का उचित मूल्य नहीं मिल रहा है इस समय वित्तीय संकट का सामना कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके कारण क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने राज्य में वित्तीय संकट का सामना कर रहे कपास उत्पादकों के पक्ष में कोई पहल की है ;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्री (श्री जी० वेंकट स्वामी) : (क) जी नहीं । सभी किस्म की कपास की कीमतें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी अधिक बनी रही है । न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों को पर्याप्त लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने के लिये निर्धारित की जाती है ।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते ।

हस्तशिल्पों के विकास के लिये वित्तीय सहायता

4469. श्री इकबाल सिंह : क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में विशेषकर पंजाब में आठवीं पंचवर्षीय योजना की अवधि के दौरान अब तक हस्तशिल्पों के विकास के लिये कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा देश के विभिन्न राज्यों विशेषकर पंजाब में हस्तशिल्पों के विकास और उनको बढ़ावा देने के लिये कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है ; और

(ग) क्या सरकार चालू वित्त वर्ष के दौरान पंजाब के शिल्पकारों को कोई विशेष राहत प्रदान करने का विचार रखती है?

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (के) हस्तशिल्प राज्य का विषय है । तथापि, पंजाब राज्य सहित देश में हस्तशिल्प के

विकास के लिये केन्द्रीय सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 100.05 करोड़ रुपये की राशि व्यय की है, जिसमें से 79.32 लाख रुपये की राशि पंजाब के हस्तशिल्प के विकास के लिये विभिन्न संगठनों को सहायता अनुदान के रूप में प्रदान की गई है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा विभिन्न राज्य हस्त-शिल्प निगमों/संगठनों को प्रदान की गई वित्तीय सहायता (राज्य वार) के विस्तृत ब्यौरे संलग्न विवरण में दिये गये अनुसार है (सीधे देखिये)।

(ग) पंजाब के शिल्पियों को विशेष राहत देने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, प्रशिक्षण डिजाइन कार्यशाला, विपणन संबंधी कार्यक्रम, शिल्प विकास केन्द्र की स्थापना तथा शिल्पियों के कल्याण के लिये राज्य हस्तशिल्प निगमों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

विवरण

विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के हस्तशिल्प निगमों/शीर्ष सहकारी समितियों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों को पिछले तीन वर्षों के दौरान रिलीज की गई वित्तीय सहायता।

(लाख रुपये में)

क्रमांक	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	1992-93	1993-94	1994-95
1	2	3	4	5
1	आंध्र प्रदेश	36.16	102.03	86.01
2	अरूणाचल प्रदेश	3.31	4.12	—
3	असम	15.13	27.56	42.96
4	बिहार	10.91	17.75	13.50
5	गोवा	8.81	19.74	7.08
6	गुजरात	18.36	29.77	53.14
7	हरियाणा	28.22	62.59	45.95
8	हिमाचल प्रदेश	10.78	16.79	39.91
9	जम्मू व कश्मीर	43.41	37.94	49.95
10	कर्नाटक	18.21	36.61	40.61
11	केरल	83.35	68.20	46.77
12	मध्य प्रदेश	35.08	85.76	100.51
13	महाराष्ट्र	16.95	29.30	37.72
14	मणिपुर	8.10	17.39	8.29
15	मेघालय	1.01	2.28	2.09
16	मिजोरम	0.49	1.99	3.00
17	नागालैंड	9.71	10.33	3.09

1	2	3	4	5
18	उड़ीसा	52.87	100.20	80.52
19	पंजाब	16.40	47.52	15.33
20	राजस्थान	31.38	36.31	30.76
21	सिक्किम]	2.50	1.86	0.97
22	तमिलनाडु	52.29	63.66	69.84
23	त्रिपुरा	9.67	4.46	8.06
24	उत्तर प्रदेश	108.99	214.73	352.85
25	पश्चिमी बंगाल	36.84	59.59	57.27
26	अंडमान और निकोबार	1.11	0.62	1.43
27	दिल्ली	60.44	117.77	106.79
28	पांडिचेरी	5.11	7.77	4.07
	योग :	725.59	1224.64	1308.51

राष्ट्रीय वस्त्र निगम द्वारा भूमि और भवनों की बिक्री

4470. **श्री अजीत जोगी:**
श्री एस. एस. सुरजेवाला :

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वस्त्र निगम ने संसाधन जुटाने के लिये हाल ही में अपनी भूमि और भवनों को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो उसका एकक-वार ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्य योजना तैयार की गई है ।

वस्त्र मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों ने एन टी सी. की मिलों के आधुनिकीकरण के लिये योजनायें तैयार की हैं। एन टी सी पर श्रम मंत्रालय की विशेष त्रिपक्षीय समिति ने अन्य बातों के साथ सिफारिश की है कि एन टी सी की मिलों तथा अधिग्रहीत मिलों को टैक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशनों द्वारा यथा प्रस्तावित आधुनिकीकरण के द्वारा सक्षम बनाया जा सकता है और यह कि एन टी सी मिलों की बेरगी भूमि तथा परिसंपत्तियों को बेचा जाय और उससे प्राप्त धन को प्रबंधन द्वारा आधुनिकीकरण, कार्य-शील पूंजी आदि के लिये प्रयोग किया जाए । एन टी सी के लिये सर्वेक्षण प्रकार की योजना सरकार के विचाराधीन है । चूंकि एन टी सी के 9 में से 8 सहायक निगमों के मामले बी आई एफ आर के पास भेजे गये है, सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भी योजना को कार्यान्वयन से पूर्व बी आई एफ आर का अनुमोदन अपेक्षित होगा ।